



कुमार कृष्णन

इस चुनाव में हाल के वर्षों में राजनीति व पूँजीपतियों के नये उमरे समीकरण के चलते इस क्षेत्र पर वर्धम स्थापित करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। इस बाट भाजपा पूरे जोश के साथ झारखंड का चुनाव जीतने के लिये वैसी ही आमादा दिखी, जैसी वह छत्तीसगढ़ और ओडिशा में थी जहां उसने जीत दर्ज करने के लिये साए पैतरे लगाये और सफलता पायी थी।

झारखंड में आदिवासी वोट
निर्णयिक होते हैं।
झारखंड में एक तिहाई से
ज्यादा (28) अनुसूचित
जनजाति सीटें हैं। आबादी
का 26 फीसदी हिस्सा
आदिवासी है। 21सीटों में
आदिवासियों की आबादी
कम से कम एक लाख है।
इन सीटों पर झामुमो की
अच्छी पकड़ है। भाजपा
इसे तोड़ने में सफल नहीं
रही।

संपादकीय

उक्सावे की राजनीति

पश्चिमी उप्र के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दोरान हुई हिस्सा और तीन लोगों की मौत वाकई चिंता की बात है। पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने व लाटी चार्ज के बावजूद उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को फूँक डाला तथा पुलिस बल पर पथराव किया। इसमें पुलिस वालों समेत तकरीबन बीस लोग घायल भी हो गए। ज्ञात है कि स्थानीय अदालत के अधिकारों के बाद जामा मस्जिद के गर्देश्वारा का क्षेत्र आज



इन लोगों का मर्शा लबा कानूना लड़ाई की है। हालांकि इन लोगों का दावा है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दूसरे, सर्वे के दौरान मस्तिष्क कमेटी के सदस्यों समेत उनके बचपन से भी मौजूद थे। घटना से पहली रात में सारा सर्वे शारीरिक निपट चुका था। स्थानीय अधिकारियों को अदेशा है, भीड़ किसी उकसावे के बाद जमा हुई। यह मस्तिष्क कब बनी, इसे लेकर भी विवाद है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी मरम्मत का काम बाबर द्वारा कराया गया था। क्योंकि इसकी निर्माण शैली मुगलकालीन नहीं है। संभावनाएं हैं कि यह तुगलक काल में बनी हो। फिलहाल यह संरक्षित इमारत पुरातत्व सर्वे की निगरानी में है पर यह विवादित स्थल है। कुछ समय पहले हिन्दू समुदाय यहां जबरन पूजा करने भी जा चुका है, परंतु पहली बार मामला अदालत में ले जाने को राजनीतिक विवाद बनाकर सुरिखियां समेटने का काम अधिक लगता है। मस्तिष्क के सामने की तरफ हिन्दू तो पिछवाड़े, मुसलमानों की बरस्ती है। जहां हमेशा नियमित नमाज पढ़ी जाती रही है। मायूली विवाद बने रहने के बावजूद कभी इस तरह का कोई नाव नहीं हुआ। अयोध्या में विवादित स्थान पर मंदिर बनने के बाद से राजनीतिक लाभ के लोभ में इसे फॉमूले के तौर पर प्रयोग किए जाने की मंशा अधिक लग रही है। राज्य सरकार या विपक्ष को यह शोभा नहीं देता। शार्ट-व्यवस्था बनाए रखने और सभी नागरिकों को सुरक्षा देने का जिम्मा निभाने में उसे कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस तरह के धार्मिक विवादों से देश की छवि बिगड़ती है।

सूक्ति

विजयी व्यक्ति स्वभाव से, बहिर्मुखी होता है। पराजय व्यक्ति को अन्तर्रुखी बनाती है। – प्रेमचंद
जो कर्म छोड़ता है वह गिराता है, कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह चटाता है। – महात्मा गांधी

छाड़ता है वह चढ़ता है। - महात्मा गांधी

भाजपा के हिंदूत्व पर भारी पड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी कार्ड

व नाच्छादित, खनिज संपदा से भरपूर और आदिवासी बहुल झारखण्ड के अब तक के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है, जब जनता ने लगातार दूसरी बार किसी दल को सत्तासीन होने का जनादेश दिया है। यहां ईडिया गठबंधन ने 81 सीटों में से 56 सीटें जीतीं, जबकि राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन 24 सीटों पर सिमट गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने सबसे अधिक सीटें (34) हासिल कीं, जबकि कांग्रेस ने 16, राष्ट्रीय जनता दल ने 4 और सीपीआई (एमएल) ने 2 सीटें जीतीं। वहाँ, दूसरी तरफ तीन सीट के नुकसान के साथ भाजपा ने 21, दो के नुकसान के साथ एजेस्यू ने एक सीट हासिल की। पहली बार एक सीट जेडीयू के खाते में गई। इनके अन्य सहयोगियों को भी दो सीटों का नुकसान हुआ, उन्हें केवल एक सीट मिली। वहाँ, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 में झारखण्ड में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा को 30, भाजपा को 25, कांग्रेस को 16, जेवीएम को तीन तथा एजेस्यू को दो और आरजेडी को एक सीट मिली थी। झारखण्ड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समाप्त हो जागा।

ज्ञानरात्र होना। इस चुनाव में हाल के वर्षों में राजनीति व पूँजीपतियों के नये उभरे समीकरण के चलते इस क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। इस बार भाजपा पूरे जोश के साथ झारखण्ड का चुनाव जीतने के लिये वैसी ही आमादा दिखी, जैसी वह छत्तीसगढ़ और ओडिशा में थी जहां उसने जीत दर्ज करने के लिये सारे पैरें लगाये और सफलता पायी थी। झारखण्ड में आदिवासी वोट निर्णयक होते हैं। झारखण्ड में एक तिहाई से ज्यादा (28) अनुसूचित जनजाति सीटें हैं। आबादी का 26 फीसदी हिस्सा अदिवासी है। 21सीटों में आदिवासियों की आबादी कम से कम एक लाख है। इन सीटों पर ज्ञामुकों की अच्छी पकड़ है। भाजपा इसे तोड़ने में सफल नहीं रही। इस बार झारखण्ड में चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह, अमित शाह ने 16, योगी आदित्यनाथ ने 14 सभाएं कीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिंमंत बिस्वा सरमा ने तो झारखण्ड में ही डेरा डाल रखा था। भाजपा के कई धूंसंधर नेताओं ने झारखण्ड में धुआंधार प्रचार किया। संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर भाजपा काफी आक्रामक रही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि झारखण्ड में भाजपा की सरकार बनाइए, घुसपैठियों को उल्टा लटका देंगे। उन्होंने घुसपैठियों को ही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का वोट बैंक बताया। जमशेदपुर में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वोट और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने चंपाएं सोरेन और सीता सोरेन के अपमान को आदिवासियों का अपमान बताया। भाजपा ने रुटंगे तो कटोगेर का नारा देकर घुसपैठ की चर्चा करते हुए हिंदुत्व का कार्ड खेला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे बंटेंगे तो कटोगे को भाजपा के नेताओं ने इस चुनाव में खूब उछाला। यह नारा बीजेपी के लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ। वहीं, ईडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी की छह सभाओं के अलावा लगभग पारा जोर हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कलपना सोरेन ने ही लगाया। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पूरा यादव ने स्टार प्रचारक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उन्होंने पचीस दिनों तक यहां कैंप कर

A photograph showing a woman in a red sari with a pink and orange patterned border on the left, and a man with a long, full grey beard and glasses on the right. Both individuals are smiling and making a peace sign with their hands. They are positioned in front of a group of people, some of whom are partially visible in the background.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी योजनाओं की चर्चा के साथ आदिवासी कार्ड खेला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी कार्ड भाजपा के हिंदुत्व कार्ड पर भारी पड़ गया। आदिवासियों का भरोसा गुरुजी शिव श्रू सेरेन के पुत्र हेमंत सेरेन पर ही रहा। झारखंड में हेमंत सेरेन के पक्ष में सहानुभूति भी काफी प्रभावी रहा। हेमंत सेरेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश करते रहे कि आदिवासी चेहरे को कुचलने के लिए किस तरह उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया। इसमें वे कामयाब भी रहे। कई विधानसभा सीट पर 40 प्रतिशत से अधिक आदिवासी मतदाता हैं। वे एकजुट होकर उनके पक्ष में खड़े हो गए।

हेमंत सेरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सेरेन सामने आईं और जहां-जहां गईं, वहाँ उन्होंने पति के साथ ज्यादी की बात समझाने की कोशिश की। चुनाव प्रचार के दौरान मईयां सम्मान योजना की राशि दो हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 2, 500 रुपये करने की चर्चा भी उन्होंने खुब की। कल्पना ने सरना धर्म कोड की भी बात की और यह भी कहा कि बींजेपी ने नेता बाहर के हैं, वे हमारी भाषा-संस्कृति तक नहीं जानते। ये भला हमारे लिए क्या नीतियां बनाएंगे। अपने सहज व सरल अंदाज से खासकर महिलाओं से संवाद करने में वे सफल रहीं। वे गांडेय सीट से चुनी गई हैं। महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं का भी असर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गया। बेरोजगार महिलाओं के लिए मासिक सहायता, स्कूली लड़कियों को मुफ्त साइकिल, अकेली महिलाओं को नकद सहायता जैसी योजनाओं ने आदिवासी और कमजोर वर्ग की महिलाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में लाने का काम तो किया ही, इसके साथ मईयां सम्मान योजना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को सालाना 12, 000 रुपये दैने वाली इस योजना तथा सर्वजन पेंशन योजना ने हेमंत के पक्ष में संजीवनी का काम किया। फिलहाल झारखंड की करीब पचास लाख से अधिक महिलाओं को मईयां सम्मान योजना के तहत 2, 000 रुपये प्रतिमाह की मदद दी जा रही है। चुनाव के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस राशि को बढ़ाकर 2, 500 रुपये कर दिया था। जबकि, गोणों दीदी योजना के तहत भाजपा ने 2, 100 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया था। बिजली बिल माप करना भी झारखंड

मुक्ति मोर्चा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। सरकार बनने पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का भी वादा किया गया। आदिवासियों की भाजपा से नाराजगी की कई वजहें रहीं। पहली यह कि वे जानते हैं कि भाजपा की नजरें यहाँ की खनिज-सम्पन्न जमीनों और जंगलों पर हैं जिन्हें वह अपने करोबारी मित्रों को देना चाहती है। फिर, जब यहाँ भाजपा शासन था और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस दौरान 2016 में छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम और संथाल परगना अधिनियम में बदलाव की कोशिशें की गयीं जिनका सीधा नुकसान आदिवासियों को होने वाला था। सितंबर 2012 में बनी झारखण्ड सरकार की ऊर्जा नीति अक्टूबर 2016 में बदल दी गई।

इसके प्रावधानों में मामूली संशोधन किए गए और रघुवर दास की कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी। इससे पहले झारखण्ड की भाजपा सरकार ने कई सर्वे नहीं कराया और न किसी विशेषज्ञ कमेटी ने उसे ऐसा करने की सलाह दी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री और झारखण्ड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति एक समृद्ध को पायदा पहुंचाने के लिए बदल दी। इसरकार ने कई स्तरों पर गडबड़ी की, न केवल ऊर्जा नीति बदली बल्कि जमीन की कीमत के निर्धारण, जनसुनवाई और पर्यावरण सुनवाई में भी फजीरवाड़ा किया गया। एनटीपीसी, डीवीसी (दामोदर घाटी निगम) और नेशनल प्रिड से तो सरकार बिजली खरीदती ही है। अदाणी समूह के झारखण्ड से बाहर स्थित प्लाट से 400 मेगावॉट बिजली खरीदने से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। ये भाजपा के नकारात्मक पक्ष थे। चुनाव में आदिवासियों के बोत लेने के लिये प्रधानमंत्री ने नेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह समेत सारी भाजपा उन्हें यह कहकर डराती रही कि कांग्रेस-झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई तो उनकी जमीनें घुसपैठियेह हडप लेंगे। यह डर झारखण्ड के साथ पश्चिम बंगल के आदिवासियों को भी दिखाया जाता रहा। भाजपा के अनुसार ये बांगलादेशी घुसपैठिये होंगे। उसका दावा है कि भाजपा की सरकार बरी तो आदिवासियों की जमीनों को हडपने से रोकने के लिये कानून लाया जायेगा; जबकि आदिवासी जानते हैं कि उपरकै उल्लिखित दोनों अधिनियम इस मामले में पर्याप्त सक्षम हैं इसलिये इन इलाकों में भाजपा की सभाएं भी फीकी रहीं।

घुसपैठ का डर दिखाकर भाजपा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का पुराना खेला कर रही थी ताकि हिन्दू-मस्लिम कार्ड खेला

जा सके, तो वहाँ वह आदिवासियों को हिन्दू बतलाकर उसे वैमनस्य के खेल में एक पार्टी बना रही है। अमित शाह ने सरायकेला विधानसभा के आदित्यपुर की सभा में कहा कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा - कांग्रेस की सरकार आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने जा रही है। हँ उनके अनुसार भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। चंपई सोरेन के प्रति सम्मान दिखाकर आदिवासियों के बोट पाने का भी प्रयास भाजपा ने किया तभी तो शाह कह रहे थे कि हझारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन का अपमान किया है।

ह्यामाटी पुत्रों की पार्टीहू वाली छवि के कारण झारखंड मुक्ति

मार्चा (जेएमएम) का इस पर बोलबाला है। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर बने इस प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास राजनीतिक अस्थिरता तथा व्यापक प्रश्नाचार का रहा लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में न केवल स्थिरता दी बल्कि जमीनी स्तर पर भी जमकर काम किया। अदित्यमिश्रोंके उत्तरान द्वेष वे बतौर मुख्यमंत्री

काम निकाला। आदिवासीयों के उत्थान हुए व बतार मुख्यमन्त्री बेहद सक्रिय रहे। राज्य के सर्वांगीन विकास के अलावा वे जल, जंगल व जमीन पर स्थानीयों के हक्कों की लड़ाई लड़ते रहे। इसलिये वे भाजपा की अंगों में खटकते रहे। उन्होंने इस राज्य में भाजपा का द्वाया-अपरेशन लोटसक्ल नाकाम कर दिया। कथित जमीन घोटाले में जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से छापे डलवाकर कई माह तक जेलों की सलाखों के पाठे डाल दिया गया था, तब उनकी जगह पर बिठाये गये चंपई सोरेन के जरिये भाजपा ने सरकार गिराने की कोशिश की। जेल से बाहर आने पर जब उन्होंने अपना पद वापस सम्हाला तो चंपई सोरेन ने अपने कथित अपमान से नाराज होकर दल छोड़ दिया। फिर वे भाजपा में चले गये जहां हेमंत की भाभी सीता सोरेन पहले से आ चुकी थीं। इनके जरिये सरकार गिराने की भाजपायी कोशिशें भी नाकाम रहीं।

हेमंत सोरेन की यह जीत आदिवासीयत की एक बहुत बड़ी जीत है। उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, मोदी, शाह, शिवराज, हेमंत, योगी सहित न जाने किनते दिग्गज नेता लगे थे। अब इस बड़ी जीत को हेमंत सोरेन को भरपूर सम्मान देना होगा, जनता की आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उत्तरना होगा और भाजपा को इस हार को विनम्रता से स्वीकार करना होगा।

پاکستان میں ایم ران کے لیے پردازش اور 政治ی سکونت

सोचने पर मजबूर कर रहा है। पड़ोसी देश इसलिए चिंतित होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हिंसा होने के बाद सीमा पर घुसपैठ जारी हो जाती है। इससे निपटने के लिए सीमा पर अलर्ट रहना होता है। बहरहाल पाकिस्तान में इमरान समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) कार्यक्रमार्थी ने आंदोलन को असरकारी बनाने के लिए इस्लामाबाद कूच किया, इससे हिंसा और टकराव की घटनाएं सामने आई हैं। इमरान की पती बुशरा बीबी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि पति की रिहाई तक इस्लामाबाद में जमी रहेंगी। इससे जनता और सरकार में टकराव की स्थिति बनती जा रही है। इसके चलते शहबाज सरकार ने सुझा के मद्देनजर इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर प्रदर्शनकारियों को हाद में रहने का संदेश दे दिया है। रेड जोन एरिया में प्रधानमंत्री आवास, संसद और दूतावास समेत महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों को शामिल किया गया है। पाकिस्तानी सेना की तैनाती कर दी गई है और सरकार ने अपने लोगों को अपने दफ्तरों से बाहर निकाला।

को रेड जोन के अंदर देखा गया तो उसे गोली मार दी जाएगी। खास बात यह है कि मौजूदा प्रदर्शन के दौरान करीब 30,000 से ज्यादा इमरान समर्थक राजधानी में मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने की वजह से कई स्थानों पर झङ्गिये भी हुई हैं, और इसमें जहां करीब आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है तो वहीं एक पुलिसकर्मी की मौत की भी खबर आई है। ऐसे मैं कब स्थिति विस्फोटक हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले साल से ही रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल के अंदर से ही 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन के लिए करो या मरो का आह्वान किया था। इसी के साथ ही इमरान ने अरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने 26वें संसोधन को तानशाही शासन को बढ़ावा देने वाला बताया। इस समय इमरान के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें दोषी भी ठहरा दिया गया है, जबकि कुछ मामलों में सुनवाई जारी है। ऐसे में जारी विरोध

मुद्दा : प्रदेशन से चाहिए मूकित

जबकि विदेशों में राजमार्गों पर होने वाले हादसों के प्रति वहाँ की सरकारी और नागरिक काफी संवेदनशील हैं। दो वर्ष पहले जब मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्ट्री की एक सड़क हादसे में मृत्यु हुई थी तो सड़क नियमों को लेकर काफी चर्चा हुई। इस हादसे के पीछे कई कारण बताए गए, जैसे की तेज गति, हातसे की जगह सड़क का कम चाँड़ा होना, आदि। परंतु बुनियादी सवाल यह है कि किसी अपीर व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली महंगी लग्जरी कार हो या किसी मामूली ट्रक या बस द्वाइवर द्वारा चलाए जाने वाला साधारण वाहन, क्या वाहन चलाने वाले और परिवहन नियम लागू करने वाले अपने-अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं? क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में सड़क सुरक्षा और परिवहन के नियम और कानून दोनों ही काफी लचर हैं। यही कारण है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं और देशों की तुलना में काफी ज्यादा होती हैं? यदि कानून की बात करें तो हमारे देश के कानून इतने लचर हैं कि सड़क दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वाहन चालक को बड़ी आसानी से जमानत भी मिल जाती है। ज्यादातर ट्रक व बस द्वाइवरों को भी इस बात का पता है कि उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। सड़क नियम और कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी केवल ट्रैफ़िक पुलिस की नहीं होनी चाहिए। इनको लागू करने के लिए समय-समय पर जागरूकता

देश देना चाहिए कि जो कैमरे तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों का चालान करते हैं, उनसे अधिक काम भी लिया जा सकता है। स्पष्ट कैमरे की तकनीक की बात करें तो उसमें लगे रेडर से एक सिग्नल जाता है जो केवल तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी की ही फोटो खींचते हैं। यदि इसी तकनीक में थोड़ा सा सुधार किया जाए तो वही कैमरा कई ट्रैफिक उल्लंघनों की फोटो भी खींच सकता है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आज से कुछ वर्ष पहले मैं लंदन की यात्रा पर था तो वहाँ मेरे स्थानीय मित्र ने गाड़ी को राजमार्ग पर लाने से पहले चश्मा लगा लिया। मेरे पृथ्वी पर उन्होंने बताया कि, 'मेरी गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस पर जो फोटो लगी है उसमें मैंने मामूली नंबर का नजर का चश्मा पहना हुआ है। यदि मैं बिना चश्मे के गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा चालान हो जाएगा।' उनका मतलब यह था कि जगह-जगह लगे कैमरे हर पहलू को पकड़ लेते हैं। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में एक से बढ़कर एक गुणवत्ता वाले कैमरे उपलब्ध हैं जो इन सभी पहलुओं को पकड़ सकते हैं। जरूरत केवल सही सोच और पहल करने की इच्छा की है। देखना यह है कि हमारे देश में ऐसे बदलाव कब होंगे? केवल चुनावी घोषणाओं के चलते नये-नये राजमार्ग खोलने से कुछ नहीं होगा। सड़क और यातायात नियमों को सख्ती से लागू भी किया जाए। शायद तभी हमारे देश में सड़क दृष्टनाओं में कमी आए।

